Government in the country for the welfare and development of women and Girl Child. Attempts are also being made to project positive images of the girl child so as to bring about changes in societal attitudes towards them. The Government has also initiated media campaigns to generate awareness on various issues relating to girl child. The National Plan of Action for the SAARC Decade (1991-2000 A.D.) for the girl child focussing on the survival, protection and development of the girl child has been formulated. A special set of interventions for adolescent girls has been institutionalised through the ICDS structure.

Government has enacted the Pre-Natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse) Act, 1994 which came into force with effect from 1.1.96 and provides that use of diagnostic techniques for the purpose of pre-natal sex determination leading to female forticide is a legal offence.

Rehabilitation of Women and Child Labour in Bidi Sector

*503. SHRI YERRA NARAYANASWAMY: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) the approximate percentage of women and child labour in the bidi sector;

(b) whether Government have any plans to rehabilitate such labour in other sectors; and

(c) if so, the plans to reduce child labour in the bidi sector?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) to (c) As per the Report on Working and Living Conditions of Workers in Beedi Industry in India prepared by Labour Bureau (1995), it is estimated that 65.9% of workers in the bidi industry are women and 1% are children. Bidi and Cigar Workers (Conditions of Employment) Act, 1966 regulates the working conditions of all bidi and cigar workers including women workers. Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986, prohibits employment of children in the process of bidi making. A programme for Elimination of Child Labour in all hazardous occupations including beedi making has been launched. So far 76 National Child Labour Projects covering about 1.5 lakh children in child labour endemic States have been sanctioned. These Projects involve identification of children employed in such industry, withdrawing them from work and putting them in special schools established for this purpose where they are given basic education and vocational training. Health checks, nutrition and payment of stipend are the other areas of concern addressed under the Programme.

ESI Hospitals and Dispensaries in Maharashtra

*504. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) total number of ESI hospitals and dispensaries which are functioning in various parts of the State of Maharashtra with district-wise details thereof;

(b) whether Government have any proposal to upgrade these dispensaries to bed hospitals in the near future;

(c) if so, details thereof; and

(d) the number of ESI dispensaries in Nagpur which are likely to be upgraded into 50 and more bed hospitals?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

No. of ESI Hospitals & Dispensaries in the State of Maharashtra, District-wise

S. No.	Name of the District	No. of ESI Hospitals	Dispensaries
1.	Bombay	8	20
2.	Pune	1	4
3.	Solapur	1	4
4.	Kolhapur	—	5
5.	Satara	—	1
6.	Nasik	1	5
7.	Sangli	—	2
8.	Jalgaon	—	4
9.	Dhule	—	2
10.	Aurangabad	—	4
11.	Nanded	—	2
12.	Nagpur	1	16
13.	Akola	—	3
14.	Wardha	—	2
15.	Amravati	—	1
16.	Chandrapur	—	1
	Total	12	76

There is no proposal from the Government of Maharashtra received in the ESIC for upgradation of any ESI dispensaries as hospitals.

सरकार के एकाधिकार में रखे जाने वाले क्षेत्र

*505. **श्री राम जेठमलानी:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि किलोक उद्यम विभाग ने यह सलाह दी है कि आठ मूल क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक उद्यमों को सरकार के एकाधिकार में ही रखा जाये;

(ख) यदि हां, तो इन आठ मूल क्षेत्रों में कौन-कौन से क्षेत्रों को शामिल किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने इस उपरोक्त सलाह पर विचार कर कोई निर्णय भी लिया है;

(घ) यदि हां, तो निर्णयों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में निर्णय कब तक ले लिये जाने की संभावना है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

(ग) वर्तमान नीति के तहत सरकारी क्षेत्र के लिए केवल 6 क्षेत्र आरक्षित हैं। इस सूची को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उपभोक्ता मदों के मुद्रित और फुटकर मूल्यों में अन्तर

*507. **श्री नागमणि:**
श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:

क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न घरेलू किराना वस्तुओं और उपभोक्ता मदों पर मुद्रित फुटकर मूल्यों तथा इनके वास्तविक विक्रय मूल्यों में बड़ा अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय भंडार और सुपर बाजार में भी इन मदों पर अधिक मूल्य दर्शाया जाता है; और

(घ) इस तरह की कार्यविधि से उपभोक्ताओं को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जोन का विचार है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) और (ख) किसी पैकेज पर मुद्रित मूल्य में कर, भाड़ा तथा कमीशन जैसे विभिन्न अवयव शामिल होते हैं। मुद्रित मूल्य केवल अधिकतम मूल्य होता है और वास्तविक बिक्री मूल्य इन कारकों को देखते हुए अधिकतम खुदरा मूल्य से कम हो सकता है।

(ग) मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार सुपर बाजार और केन्द्रीय भंडार में घरेलू किराना वस्तुओं तथा उपभोक्ता वस्तुओं की बहुत सारी किस्मों के बिक्री मूल्य अधिकतम खुदरा मूल्य से कम पर नियत किए जाते हैं। उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए केन्द्रीय भंडार तथा सुपर बाजार उस मार्जिन पर वस्तुएं बेचते हैं जो प्रापण लागत के 9% से अधिक न हो बशर्ते कि बिक्री मूल्य अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक न हो।

(घ) पैकेज पर घोषित किए गए अधिकतम खुदरा मूल्यों से अधिक मूल्य वसूल करने के मामलों का पता लगाने के लिए खुदरा बिक्री केन्द्रों का अचानक निरीक्षण और जांच की जाती है। दोषी पाये जाने वालों के विरुद्ध बाट तथा माप मानक अधिनियम, 1976 तथ बाट तथा माप मनाक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 के प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाया जाता है।